

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 4643
31 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए
स्मार्ट शहर मिशन का कार्यान्वयन

4643. श्री जयंत सिन्हा :

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्मार्ट शहर मिशन (एससीएम) के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) झारखंड के रांची में फरवरी 2022 तक इस परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार झारखंड के और शहरों को एससीएम में शामिल करने हेतु इसके दायरे का विस्तार करने का विचार कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) सरकार द्वारा इस मिशन के अंतर्गत की जाने वाली सभी पहलों में पर्यावरणीय संवहनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) जलवायु स्मार्ट शहर आकलन संरचना (सीएससीएएफ) के अंतर्गत शहरों को मिले अंकों का ब्यौरा क्या है और सीएससीएएफ-2.0 के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): भारत सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) आरंभ किया। जनवरी 2016 से जून 2018 तक प्रतियोगिता के 4 दौर के माध्यम से 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है। 4 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार ने 100 स्मार्ट शहरों के लिए 29,213.60 करोड़ रुपये जारी किए हैं। जिनमें से 25,177.65 करोड़ रुपये (86%) का उपयोग किया जा चुका है। 4 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, 100 स्मार्ट शहरों ने 1,91,238 करोड़ रुपये की 6,928 परियोजनाओं की निविदा दी है; 1,65,503

करोड़ रुपये की 6,282 परियोजनाओं में कार्य आदेश जारी किए गए हैं; 59,958 करोड़ रुपये की 3,576 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। मई, 2016 में चयन प्रक्रिया के फास्ट-ट्रैक राउंड में स्मार्ट सिटी के रूप में विकास के लिए रांची शहर का चयन किया गया था। 4 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार ने रांची स्मार्ट सिटी के लिए 490 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिनमें से स्मार्ट सिटी ने 466 करोड़ रुपये (95%) का उपयोग किया है। रांची स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गई है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

डीपीआर चरण		निविदा चरण		कार्य आदेश चरण		कार्य पूर्ण		कुल	
परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि
7	148.03	1	586.46	20	2,209.37	6	417.49	34	3,361.35

(स्रोत: एससीएम भू-स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (जीएमआईएस), 4 मार्च 2022 तक)

(ग) और (घ): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ड): स्मार्ट सिटी मिशन में जलवायु अनुकूल शहरों के निर्माण के लिए समाधान एक प्राथमिकता है। 4 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, मिशन 26,794 करोड़ रुपये की 789 स्मार्ट रोड परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, गैर-मोटर चालित परिवहन और बेहतर पैदल यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने के परिणामस्वरूप भीड़भाड़, पर्यावरण प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों में कमी आई है। इसी प्रकार, 1,301 करोड़ रुपये की लागत वाली 95 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। 24,029 करोड़ रुपये की 316 स्मार्ट जल परियोजनाओं और 17,983 करोड़ रुपये की 268 स्मार्ट अपशिष्ट जल परियोजनाओं को शुरू किया गया है। इनसे और इस तरह की पहलों से ग्रीनहाउस गैसों, प्रदूषण में कमी आती है और संसाधन संरक्षण मिशन का हिस्सा हैं।

(च): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद 2019 में जलवायु स्मार्ट सिटी आकलन ढांचा (सीएससीएएफ) आरंभ किया है। यह ढांचा शहरों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जलवायु-संवेदनशील विकास पद्धतियों को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक तंत्र के रूप में कार्य करता है। सीएससीएएफ 2.0 सितंबर से दिसंबर 2020 तक आयोजित किया गया था। आकलन ढांचे में पांच विषयगत क्षेत्रों में 96 डेटा बिंदुओं को कवर करने वाले 28 विविध संकेतक शामिल हैं जिनमें (i) शहरी

नियोजन हरित आवरण और जैव विविधता (ii) ऊर्जा और हरित भवन (iii) आवाजाही और वायु गुणवत्ता। (iv) जल प्रबंधन; और (v) अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन शामिल है। 100 स्मार्ट शहरों, राजधानी शहरों और 500,000 से अधिक आबादी वाले शहरों सहित कुल 126 शहरों ने 2020 के आकलन चक्र में सफलतापूर्वक भाग लिया। सीएससीएएफ 2.0 के परिणाम <https://niua.org/c-cube/c-cube-documents> पर देखे जा सकते हैं।
